

AMAR UJALA

DELHI

23 APRIL 2026

हिसार एयरपोर्ट : 5 मिनट के अंतराल पर विमानों के उड़ान संचालन के लिए तैयार सिविल एविएशन विभाग की एसीएस ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण

हिसार। सिविल एविएशन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने बुधवार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों की बैठक ली। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि हिसार हवाई अड्डे से प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर हवाई जहाज लैंड और टेक ऑफ हो सकते हैं। केट 2 और ऑटो पायलट मोड पर लैंड करने के लिए आईलैंड की अनुमति मिलनी बाकी है। उन्होंने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए परिसर में बेहतर बस सेवा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि लंबित अनुमति के लिए डीजीसीए से



निर्माण कार्यों व भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते अतिरिक्त मुख्य सचिव

निरंतर संपर्क में रहें। अभी महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और अयोध्या के लिए उड़ान सेवा उपलब्ध है। जल्द ही

अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवा आरंभ करना प्रस्तावित है। इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर के पहले चरण की स्थापना के उपरांत यहां पर काफी संख्या में हवाई जहाजों का परिचालन होगा।

उन्होंने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए परिसर में बेहतर बस सेवा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक के उपरांत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हवाई अड्डा परिसर के रनवे टर्मिनल बिल्डिंग व एटीसी बिल्डिंग के निर्माण कार्यों के संबंध में भी निरीक्षण किया। उपायुक्त महेंद्र पाल, अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, एयरपोर्ट डायरेक्टर ओपी सैनी, डीएम अजय सक्सेना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैप्टन एस गिल मौजूद रहे।

उड़ान भरने की तैयारी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

- नोएडा एयरपोर्ट से मई के अंतिम सप्ताह में विमानों का संचालन शुरू होने की संभावना
- यापाल बोर्ड में विदेशी सीईओ बदलने पर बनी सहमति
- सितयोरिटी विलयरेस की अड़चन होगी दूर



एयरपोर्ट को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से परिचालन योग्य बनाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। डीजीसीए, बीसीएएस और अन्य विभागों के बीच निरंतर बैठकें हो रही हैं ताकि बाकी बची औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जा सकें : आरके सिंह, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ

ग्रेटर नोएडा, 22 अप्रैल (देशबन्धु)। जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जिसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है) का औपचारिक उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। इसके बाद से संचालन की तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। हालांकि, व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत अभी अंतिम चरण में अटकती हुई है। मई 2026 के अंतिम सप्ताह तक पहली उड़ानें शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसके लिए व्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिविलियरीटी (बीसीएएस) की मंजूरी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

बीसीएएस आपत्तियों का निस्तारण : 10 दिनों का लक्ष्य

एयरपोर्ट ऑपरेटर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापाल) ने एयरपोर्ट सिविलियरीटी प्रोग्राम (एएसपी)

की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। बीसीएएस ने कुछ तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज की हैं, जिन्हें अगले 10 दिनों के अंदर दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे चर्चित मुद्दा विदेशी सीईओ से जुड़ा है। वर्तमान में स्विस नागरिक क्रिस्टोफ श्नेलमैन एयरपोर्ट के सीईओ हैं, जिन्होंने छह साल से इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया

है। बीसीएएस और गृह मंत्रालय (एमएएच) की सुरक्षा नियमों के अनुसार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सीईओ पद पर विदेशी नागरिक की नियुक्ति पर आपत्ति है। सूत्रों के अनुसार, इस नियम को ढील देने की मांग खारिज कर दी गई है, जिसके चलते भारतीय नागरिक को सीईओ पद पर नियुक्त करने की संभावना मजबूत हो गई है। यह कदम उठाए बिना एएसपी की

अंतिम मंजूरी मुश्किल मानी जा रही है। एक बार एएसपी मंजूर होने के बाद ऑपरेशंस शुरू होने में लगभग 45 दिन का समय लग सकता है। मंगलवार को यापाल बोर्ड की बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिस पर भारतीय सीईओ नियुक्त करने पर विचार किया गया।

प्रारंभिक चरण में क्या होगा संचालन?

संचालन शुरू होने पर पहले चरण में देश के 17 प्रमुख शहरों के लिए घरेलू उड़ान सेवाएं उपलब्ध होंगी। रोजाना 60 से 70 फ्लाइट्स के टेकऑफ और लैंडिंग का अनुमान है। इंडीगो एयरलाइंस पहली कमर्शियल फ्लाइट संचालित करने की तैयारी में है। इससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की भीड़भाड़ वाले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बढ़ावा मिलेगा।

वर्तमान क्षमता व भविष्य की योजनाएं

पार्किंग सुविधा : फिलहाल एयरपोर्ट पर 25 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। विस्तार की योजना : 25 अतिरिक्त हेंगर बनाने का काम शुरू हो चुका है। इनके पूरा होने के बाद कुल क्षमता 50 विमानों तक पहुंच जाएगी। इंटरनेशनल टर्मिनल : डोमेस्टिक उड़ानों के साथ-

साथ अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की तैयारी भी जोरों पर है। टर्मिनल बिल्डिंग में इंटरनेशनल सेक्शन का निर्माण तेजी से चल रहा है। फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है और अगस्त 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की जा सकेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आर.के. सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से परिचालन योग्य बनाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। डीजीसीए, बीसीएएस और अन्य विभागों के बीच निरंतर बैठकें हो रही हैं ताकि बाकी बची औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जा सकें।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे उत्तर भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने वाला प्रोजेक्ट है। हालांकि, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। यदि अगले कुछ दिनों में बीसीएएस की मंजूरी मिल जाती है, तो मई के अंत तक जेवर से पहली उड़ानें आसमान छू सकती हैं। यह न केवल यात्रियों के लिए नया विकल्प होगा, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई शुरुआत भी साबित होगा।

Proposal to turn 700-acre HAL airport into global aerospace hub

10-year plan for defence-civil-space corridor at HAL Aerospace City District

BENGALURU, DHNS

A Government of Karnataka (GoK) undertaking has proposed an ambitious 10-year plan to transform the HAL Old Airport area into a global aerospace hub, aiming to position Bengaluru among the world's top aviation centres by 2036.

The proposal, titled 'HAL Aerospace Renaissance Masterplan (2026-2036)', recommends redeveloping nearly 700 acres of Hindustan Aeronautics Limited (HAL) land into

a next-generation aerospace innovation district. It envisions creating a USD 20 billion aerospace economy within a decade.

According to the document submitted by the Karnataka State Industrial and Infrastructure Development Corporation (KSIIDC) and the State Policy and Planning Commission, the project seeks support from the Union government for regulatory clearances, infrastructure funding, and a supportive policy framework.

The masterplan outlines a 10-year roadmap to establish the HAL Aerospace City District as India's first integrated defence-civil-space corridor. Key initiatives include the creation of advanced manufacturing clusters for airframes, engines, avionics, composites, and rotorcraft; development of HAL air mobility campuses; and the launch of a global training and skilling academy.

The proposal also emphasises

PROJECT PHASES		
2026-29: Regulatory approvals, land-use optimisation, and infrastructure groundwork.	2029-33: Development of MRO clusters, smart hangars, and digital aviation systems.	2033-36: Full integration of civil, defence, and space aviation systems, along with green energy adoption.
		

A file photo of the HAL Old Airport area.

building a strong ecosystem by involving global aviation majors such as Airbus, Boeing, Embraer, Rolls-Royce, GE Aerospace, and Safran, alongside Indian institutions, includ-

ing the Indian Air Force, DRDO, and ISRO.

It recommends a diversified funding model comprising government investment, public-private part-

nerships (PPPs), global collaborations, and sovereign green finance instruments.

The Karnataka State Policy and Planning Commission, which mooted the proposal, expects the project to generate over two lakh high-skilled jobs and elevate Bengaluru into the world's top five aerospace cities by 2036. The document highlights alignment with national priorities such as defence modernisation, Aatmanirbhar Bharat, and aviation self-reliance.

"The HAL Aerospace Renaissance Masterplan is a national capability-acceleration platform, not merely a state-level initiative. It directly advances India's defence preparedness, aviation self-reliance, clean energy transition, and global aerospace competitiveness," said S Mohanadass Hegde, a member of the commission, in his report submitted to Chief Secretary Shalini Rajneesh.

आइजीआइ अब ग्लोबल एविएशन हब बनने की दिशा में निर्णायक छलांग लगाने को तैयार

आइजीआइ टर्मिनल-3 के पियर-सी का घरेलू से अंतरराष्ट्रीय पियर में रूपांतरण का कार्य हुआ पूरा नागरिक उड़डयन मंत्रालय, इमिग्रेशन व सुरक्षा एजेंसियों से अंतिम मंजूरी का इंतजार

गौरव कुमार मिश्रा • जागरण

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) अब ग्लोबल एविएशन हब बनने की दिशा में निर्णायक छलांग लगाने को तैयार है। टर्मिनल-3 के पियर-सी का घरेलू से अंतरराष्ट्रीय पियर में रूपांतरण का कार्य, कई बाधाओं और समय सीमा ब्रीतने के बाद आखिरकार पूरा हो गया है। इसे शुरू करने के लिए एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को नागरिक उड़डयन मंत्रालय, इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियों से अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

परियोजना के पूरा होने की राह आसान नहीं रही। इसे मूल रूप से अगस्त-सितंबर 2025 तक, यानी सर्विचों के शेड्यूल से पहले तैयार होना था। इसके बाद मास्टर प्लान 2026 के तहत 15 जनवरी की समय सीमा तय की गई, लेकिन तकनीकी कारणों और सुरक्ष मानकों को पूरा करने के चलते यह डेडलाइन भी निकल गई। आखिरकार



आइजीआइ एयरपोर्ट टर्मिनल-3। फाइल

मार्च में निर्माण कार्य पूरा हुआ और अब अप्रैल के चौथे सप्ताह में यह संचालन के लिए तैयार है। वर्तमान में डीजीसीए, बीसीएएस, इमिग्रेशन और कस्टम्स जैसी एजेंसियों से अंतिम क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है।

पियर-सी के अंतरराष्ट्रीय बनने से 'पैसेंजर मिक्सिंग' (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का मिलना) की समस्या खत्म होगी। इसमें उन्नत इमिग्रेशन काउंटर, आधुनिक सुरक्षा स्क्रीनिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग गेट्स लगाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एयरसाइड ट्रांसफर की सुविधा है, जिससे टी-1 और टी-3 के बीच यात्रियों का आवागमन आसान होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा।

जागरण संवाददाता, गेट नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मई अंत में यात्री व कार्गो विमान सेवा शुरू हो जाएगी। देश के 17 प्रमुख शहरों के लिए नोएडा एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) को मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के प्रस्ताव को अस्वीकार करने जैसी परिस्थिति पर भी चर्चा हुई। एयरपोर्ट संचालन शुरू करने के लिए यापल कंपनी के सीईओ पद पर जल्द किसी भारतीय को नियुक्त का फैसला कर सकता है।

नोएडा एयरपोर्ट को छह मार्च को एयरोड्रम लाइसेंस मिला था। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से यात्री सेवा शुरू होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन यापल सीईओ के विदेशी नागरिक होने के कारण गृह मंत्रालय ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के प्रस्ताव को अस्वीकार कर झटका दे दिया। इससे एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोग्राम को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्वीकृति

17 प्रमुख शहरों के लिए नोएडा एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे



नोएडा एयरपोर्ट। फाइल

में पेंच फंस गया है। एयरपोर्ट से विमान सेवा जल्द शुरू करने को लेकर यापल की बोर्ड बैठक में मौजूद हालात पर चर्चा हुई। एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोग्राम की स्वीकृति के लिए यापल सीईओ पद पर भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की फैसला जल्द ले सकता है। कंपनी में सोनियर स्तर पर कई अधिकारी कार्यरत हैं। उनमें से भी किसी को सीईओ नियुक्त किया जा सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि मई के अंत तक एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो, अकासा आदि 17 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करेंगे।



Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN TIMES

DELHI

23 APRIL 2026

यापल की बोर्ड बैठक में एयरलाइंस कंपनियों से वार्ता, 17 शहरों के लिए घरेलू उड़ान की योजना पर काम शुरू अगले माह से उड़ानें शुरू करने की तैयारी



ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले महीने उड़ान शुरू करने की तैयारी है। इसे लेकर एयरलाइंस कंपनियों के साथ वार्ता की गई। एयरलाइंस कंपनियों ने शुरुआत में 17 शहरों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) की एयरपोर्ट साइट पर मंगलवार को बोर्ड बैठक हुई। इसमें एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के संबंध में आ रही रुकावट समेत अन्य प्रस्तावों



जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतरराज्यीय द्वार बनकर तैयार है। • हिन्दुस्तान

पर चर्चा की गई। मई के अंत तक एयरपोर्ट से घरेलू और कार्गो विमान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। तीन एयरलाइंस कंपनियों के पदाधिकारियों से वार्ता की गई।

शुरुआत में एयरपोर्ट से 17 फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। अब तक उड़ान के लिए शहरों का चयन नहीं हो सका है। एयरपोर्ट का 28 मार्च को प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ हो चुका है।

एयरपोर्ट परिसर में होटल दिसंबर तक तैयार होगा

एयरपोर्ट परिसर में रोजिएट होटल का निर्माण कार्य जारी है। इसे दिसंबर 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसका निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। यहां पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ान शुरू होने के बाद एयरपोर्ट कर्मचारियों, कू मैबर और एयर होस्टेस समेत यात्रियों को ठहरने के लिए इसमें विशेष इंतजाम होंगे। इसके अलावा वीवीआईपी और वीआईपी के लिए लॉज भी बनेंगे। होटल में खानपान के विशेष इंतजाम भी होंगे।

विमानों के लिए 25 नए स्टैंड बनाए जाएंगे

यापल की बैठक में निर्णय लिया गया कि एयरपोर्ट पर अगले दो वर्षों में विमानों को खड़ा करने के लिए 25 नए स्टैंड बनेंगे। इस पर 300 करोड़ का खर्च आएगा। वर्तमान में 28 स्टैंड तैयार हैं। इनमें तीन कार्गो और 25 व्यावसायिक विमानों के लिए हैं। रनवे से हर दो मिनट में एक विमान उड़ेगा।

GS यापल की बोर्ड बैठक में मई के अंत तक एयरपोर्ट से घरेलू और कार्गो उड़ान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय की आपत्तियां दूर करने का काम शुरू हो गया है। इसी माह में एएसपी को मंजूरी दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- आरके सिंह, सीईओ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड



Corporate Communications Directorate

JANSATTA

DELHI

23 APRIL 2026

नोएडा हवाई अड्डे से अगले माह उड़ानें शुरू करने की तैयारी

सत्रह शहरों के लिए घरेलू सेवा की योजना पर काम

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 22 अप्रैल।

जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। विमानन कंपनियों ने शुरुआत में 17 शहरों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। यीडा सीईओ आरके सिंह ने बताया कि यमुना इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (यापल) की मंगलवार को बोर्ड बैठक हुई।

बैठक में हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने में आ रही रुकावटों समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई और मई के अंत तक हवाई अड्डे से घरेलू और कार्गो विमान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सुरक्षा क्लीयरेंस के लिए गृह



मंत्रालय की आपत्तियों को दूर करने का काम शुरू हो गया है। विमानन कंपनियों ने शुरुआत में 17 उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। जिसका पूरा खाका तैयार करने समेत टिकट बुकिंग सेवा शुरू करने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अब तक उड़ान के लिए शहरों का चयन नहीं हो सका है। वहीं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (वकास) से उड़ान

के लिए अंतिम मंजूरी के प्रस्ताव पर विदेशी सीईओ का मसला सुलझाने पर भी अधिकारियों के बीच मंथन हुआ। एअरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम (एसपी) के लिए सभी आपत्तियां इसी माह में दूर करने का दावा किया गया। यापल की बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हवाई अड्डे पर अगले दो वर्षों में विमानों को खड़ा करने के लिए 25 नए स्टीड बनेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वर्तमान में 28 स्टीड बनकर तैयार हैं, जिनमें तीन कार्गो और 25 व्यावसायिक विमानों के लिए हैं।

हवाई अड्डे पर 10 एयरोब्रिज जोड़े गए हैं, जिससे विमान यात्री एक साथ उड़ान भर सकेंगे। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का गत 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था।



Corporate Communications Directorate

MILLENNIUM POST

DELHI

23 APRIL 2026

INDIAN CEO MANDATORY FOR GREENFIELD AIRPORTS

Home Ministry blocks foreign CEOs for airports, Jewar Airport launch hit

DIPIKA KIROLA

NOIDA: The Union home ministry has rejected a proposal to amend rules that would have allowed a foreign national to serve as chief executive of a greenfield airport, a decision that directly affects the upcoming Noida International Airport at Jewar, officials familiar with the matter said.

Current regulations mandate that the CEO of a greenfield airport in India must be an Indian citizen, primarily on aviation security grounds. A request to relax this rule was sent by the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), the aviation security regulator under the civil aviation ministry, but was declined. "The home ministry is not in favour of allowing expatriates to head greenfield airports," an official said.

The decision narrows options for the Noida International Airport, which is being developed and will be oper-



ated by Yamuna International Airport Pvt Ltd, a subsidiary of Switzerland-based Zurich Airport International AG. The airport's current CEO, Christoph Schnellmann, is a Swiss national. In the worst-case scenario, officials indicated, the operator may have to appoint an Indian national to the role.

The issue has also emerged as a hurdle to the airport's operational readiness. Although the airport has received its aerodrome licence, a key clearance—the Aerodrome Security Programme (ASP)—remains pending. Officials said the CEO

has neither received mandatory security clearance from the home ministry nor been vetted by BCAS, both of which are required for airport executives.

A spokesperson for the airport said the operator is working closely with BCAS to secure approval for the ASP. "Following this, we will coordinate with stakeholders to finalise timelines for the commencement of commercial operations. Our focus is on ensuring that all systems and processes are aligned for a safe and efficient launch," the spokesperson said, without commenting

on the CEO's clearance status.

The requirement stems from a BCAS aviation security (AVSEC) order issued on 17 January 2011, which stipulates that the CEO of Indian nationality at every greenfield airport will act as the security coordinator responsible for implementing aviation security measures.

Officials said the matter has been under discussion for several years. In 2022, a show-cause notice was issued to the airport operator for non-compliance with the AVSEC order, and a proposal to amend the rules was initiated, though it did not reach a conclusion.

The Noida International Airport, located in Jewar near Greater Noida, was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 28 March. However, following the home ministry's decision, uncertainty remains over the timeline for the commencement of commercial flight operations.



Corporate Communications Directorate

THE MORNING STANDARD

DELHI

23 APRIL 2026

Old foreign CEO rule delays operations at Noida airport

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE start of long-delayed commercial operations at the Noida International Airport (NIA) is set to be pushed further, with the Ministry of Home Affairs declining a proposal to amend a 15-year-old rule barring foreign nationals from heading new airports, a government source said. The chief executive officer at a Greenfield airport also serves as the security coordinator, making it a sensitive position. NIA currently has a Swiss CEO, Christoph Schnellmann.

The project is being executed by Yamuna International Airport Private Limited, a subsidiary of Zurich Airport International AG, making it India's first airport run by a 100% foreign entity.

A 2011 order by the Bureau of Civil Aviation Security mandates that the CEO of every Greenfield airport must be an Indian national and act as the security coordinator, responsible for implementing aviation security measures. An official said the BCAS cannot grant clearance unless the Home Min-



istry approves any relaxation.

The airport was inaugurated by PM Narendra Modi on March 28, with expectations of operations starting soon. The Directorate General of Civil Aviation had granted the aerodrome licence on March 6. However, sources said the second phase of security clearance—the Aerodrome Security Programme (ASP)—remains pending.

“The ASP documents the security framework and contin-

gency plans in case of emergencies,” a source said.

Responding to queries, the airport said in a statement, “We are working closely with the BCAS to secure approval for the ASP. Following this, we will coordinate with all stakeholders to finalise timelines for the commencement of commercial operations. Our efforts are focused on ensuring that all systems, processes, and personnel are fully aligned to deliver a safe, efficient, and seamless start of operations.”

Officials indicated that the airport may need to appoint an Indian CEO or explore alternative arrangements with the government. A Home Ministry official declined to comment, while BCAS Director General Rajesh Nirwan did not respond to repeated calls.

Airport was inaugurated by PM on March 28

The airport was inaugurated by PM Narendra Modi on March 28, with expectations of operations starting soon. The Directorate General of Civil Aviation had granted the aerodrome licence on March 6. However, sources said the second phase of security clearance—the Aerodrome Security Programme—remains pending.



Corporate Communications Directorate

NAVBHARAT TIMES

DELHI

23 APRIL 2026

नोएडा एयरपोर्ट के विदेशी CEO का मामला पहुंचा 'सेवा तीर्थ'

Maneesh Aggarwal
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्विट्जरलैंड के विदेशी सीईओ क्रिस्टोफ शनेलमान को बदलकर इनकी जगह भारतीय सीईओ को रखने का मामला बुधवार को 'सेवा तीर्थ' यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (पीएमओ) पहुंच गया। यहां इस मामले को लेकर देर शाम मीटिंग शुरू हुई। जिसमें पीएमओ के अधिकारी और नागर विमानन मंत्रालय समेत अन्य संबंधित एजेंसियों के भी अफसर पहुंचे।

नोएडा एयरपोर्ट के विदेशी सीईओ को बदलकर इनकी जगह भारतीय सीईओ को रखने वाली खबर एनबीटी द्वारा सबसे पहले 21 अप्रैल को छापने के बाद सुर्खियों में आए इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया। सूत्रों का कहना है कि भारत में पहली बार दो देशों के बीच फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए नोएडा एयरपोर्ट के विदेशी सीईओ के मामले को गंभीर मानते हुए पीएमओ ने इसके लिए अर्जेंट मीटिंग बुलाई। जिसमें सभी के पक्ष सुने गए। सूत्रों के मुताबिक, मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की विदेशी सीईओ की जगह हर सूरत में भारतीय सीईओ रखना ही होगा

■ विदेशी सीईओ क्रिस्टोफ शनेलमान को बदलकर इनकी जगह भारतीय सीईओ को रखने का मामला

■ पीएमओ में इस मामले पर देर शाम मीटिंग शुरू हुई

पर विचार-विमर्श किया गया।

सूत्रों का कहना है कि मामला यहां नोएडा एयरपोर्ट के विदेशी सीईओ क्रिस्टोफ शनेलमान को एयरपोर्ट से बाहर करने का नहीं है, बल्कि उन्हें केवल सीईओ के पद से हटाने का बताया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह तय है कि देश के तमाम हवाई अड्डों की सुरक्षा संबंधित नियम बनाने और उन्हें लागू करने वाली एजेंसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिफ्टोरिटी (BCAS) के सुरक्षा को लेकर 2011 के नियम कहते हैं कि भारत में किसी भी एयरपोर्ट का सीईओ विदेशी नहीं हो सकता।

इस पद पर हर सूरत में भारतीय नागरिक ही होना जरूरी है। ऐसे में आईबी और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सही है, अब अगर क्रिस्टोफ को नोएडा एयरपोर्ट पर बनाए ही रखना है तो उन्हें सीईओ की जगह कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब फैसला नोएडा एयरपोर्ट ऑपरेटर को लेना है।

Plan to turn HAL airport into mega aviation hub

ManuAiyappa.Kanathanda
@timesofindia.com

Bengaluru: The state govt is preparing a 10-year blueprint to turn HAL airport campus in Bengaluru into an integrated defence-civil-space aviation district, positioning the city among the world's leading aerospace hubs.

HAL Aerospace Renaissance Masterplan (2026-2036), prepared by Karnataka State Policy and Planning Commission (KSPPC) and submitted to chief secretary Shalini Rajneesh for central clearance, proposes redeveloping nearly 700 acres into a unified ecosystem combining military aviation, commercial operations, space mobility and emerging technologies. If cleared, the project aims to place Bengaluru alongside global centres such as Toulouse, Hamburg and Seattle by 2036.

The plan proposes a joint state-centre implementation authority to fast-track approvals, manage land use and coordinate across ministries. A digital control tower is also



TOI

SET TO SPREAD WINGS? The state govt admits the proposal hinges on clearance from the Centre

envisaged to track maintenance, repair and overhaul output, R&D activity, and clean energy adoption.

But the proposal hinges on central approval since the airport is administered by the ministry of defence. In a communication to the infrastructure development department, officials said, "any decisions regarding its redevelopment, land-use optimization, and integration with broader aerospace innovation activities must be taken at the level of the defence ministry."

Officials also suggested aligning the project with the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor and the Bengaluru-Mumbai Economic Corridor to strengthen trade and logistics networks.

Mohandas Hegde, KSPPC member, said that if executed through a PPP or joint venture

with global aerospace majors and national institutions, the project could generate over \$20 billion in economic output and create more than two lakh high-skilled jobs.

The blueprint suggests a key pillar is a Safran-led maintenance, repair and overhaul (MRO) ecosystem and an India-based M88 engine facility for Rafale jets. It also proposes co-manufacturing air-to-surface weapons with Bharat Electronics Ltd.

The district will integrate civil aviation, defence and space-linked systems, while introducing urban air mobility such as electric vertical take-off and landing (eVTOL) air taxis and autonomous platforms with dedicated testing corridors. The plan includes a HAL Global Training and Skilling Academy to train 20,000 technicians annually.



Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA

DELHI

23 APRIL 2026

एयर चाइना की दिल्ली-बीजिंग उड़ान फिर शुरू

बीजिंग। एयर चाइना ने मंगलवार को दिल्ली और बीजिंग के बीच अपनी नॉन-स्टॉप विमान सेवा फिर से शुरू कर दी है। कोविड-19 और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण वर्ष 2020 से दोनों देशों की राजधानियों के बीच हवाई संपर्क बाधित था।

एयरलाइन के अनुसार, यह उड़ान अब हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। सिर्फ एयर चाइना ही नहीं, बल्कि अन्य एयरलाइंस भी सेवाएं बढ़ा रही हैं। चीन ईस्टर्न एयरलाइंस ने 18 अप्रैल को कुनमिंग और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान शुरू की थी। इससे पहले नवंबर 2025 में शंघाई-दिल्ली मार्ग बहाल किया गया था। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने भी 29 मार्च से कोलकाता और शंघाई के बीच दैनिक उड़ानें शुरू कर दी हैं। एजेसी



Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA

DELHI

23 APRIL 2026

विमान ईंधन में इथेनॉल मिलाने की अनुमति, सरकार ने नियम बदले प्रदूषण कम होने के साथ तेल के आयात पर निर्भरता होगी कम

नई दिल्ली। सरकार ने विमानन सेक्टर में प्रदूषण कम करने और महंगे कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विमान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन, यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में इथेनॉल और अन्य कृत्रिम (मानव निर्मित) हाइड्रोकार्बन मिलाने की अनुमति दे दी है।

यह फैसला 'एविएशन टर्बाइन फ्यूल (मार्केटिंग का विनियमन) आदेश, 2001' में संशोधन करके लिया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) के तहत आता है। नए नियम के अनुसार, एटीएफ अब ऐसे ईंधन के रूप में माना जाएगा जो तय मानकों (आईएस 1571) पर खरा उतरता हो या फिर आईएस 17081 मानकों के अनुसार सिंथेटिक (कृत्रिम) हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाया गया हो। ब्यूरो



टिकाऊ विमानन ईंधन को बढ़ावा

दुनिया के कई देश, जैसे ब्रिटेन और जापान, पहले से ही टिकाऊ विमानन ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह ईंधन कचरे के तेल और बस, चीनी और अनाज, नगर ठोस कचरे, लकड़ी, कृषि अवशेष या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे स्रोतों से बनाया जाता है। इसे ही सिंथेटिक या मानव निर्मित ईंधन भी कहा जाता है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऐसे ईंधन के मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% तक मिश्रण करने की योजना है।



Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE

DELHI

23 APRIL 2026

AI mulls 15-20% flight cuts on fuel cost, operational hurdles

PROFIT DRAG. Deeper cuts seen in global routes as longer flight times impact aircraft use

Rohit Vaid
New Delhi

After reportedly posting a loss of around ₹20,000 crore (\$2.4 billion) in FY26, the Tata Group-led Air India is planning to curtail operations amid rising jet fuel prices and operational challenges, industry sources told *businessline*.

According to the sources, the airline is evaluating a 15-20 per cent reduction in flight operations, while at the Group level, the curtailment may be 10-15 per cent.

Air India did not respond to queries on the reported review of its flight schedule despite multiple messages and e-mails.

The proposed cut could impact more than 100 flights out of the over 1,100 daily services operated by Air India Group.

On a standalone basis, Air India currently operates more than 700 flights daily, serving multiple domestic and international destinations.

The proposed move is expected to affect airfares and



SCALING BACK. The proposed cut could impact more than 100 flights out of the over 1,100 daily services operated by the Air India Group

capacity during the peak travel season.

FARE EFFECT

Sources said international routes are expected to bear the brunt of the cuts as higher operating costs weigh on aircraft utilisation and route economics.

The airline has been reviewing capacity deployment across its network in response to mounting operational pressures, particularly on overseas routes.

In terms of sectors, the

proposed reduction is expected to be concentrated largely on long-haul routes to Europe and North America.

Industry executives said airspace diversions and route adjustments have increased flying times on several corridors, affecting fleet utilisation and limiting the number of rotations aircraft can perform within a given schedule cycle.

"Aircraft are spending more time in the air for the same route, which directly

affects utilisation and network efficiency," an industry executive familiar with the developments said.

FUEL DRAG

Besides, elevated aviation turbine fuel prices have added pressure on operating margins.

Fuel remains among the largest cost components for airlines, and sustained price increases are prompting carriers to reassess route viability and frequency planning.

Sources said the move is being framed internally as network optimisation, not a pullback from expansion.

The airline is identifying routes where temporary frequency cuts or schedule tweaks can improve cost efficiency while maintaining connectivity. The final call on the proposal may be taken at the board meeting slated for early May.

While domestic routes may see selective tweaks, industry sources expect a sharper impact on international operations, where cost pressures are higher and turnaround economics have become more challenging.



Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE

DELHI

23 APRIL 2026

Govt amends ATF regulations, allows SAF blending in jet fuel

WAR IMPACT. Oil Ministry has also updated the legal procedures for enforcement and compliance

Rishi Ranjan Kala
New Delhi

The Ministry of Petroleum & Natural Gas has notified blending of synthesised hydrocarbon such as sustainable aviation fuel (SAF) with aviation turbine fuel (ATF).

SAF is produced from renewable feedstock such as ethanol, agricultural residues, biomass, waste oils and municipal waste, and it offers a powerful pathway to decarbonise the aviation sector.

The Ministry has amended the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, to allow the blending of ethanol in jet fuel.

In a notification on April 17, 2026, it said, "Aviation turbine fuel is a complex mixture of hydrocarbons conforming to IS 1571 specification or its blend with synthesised hydrocarbons."



WIN-WIN. This amendment lays the foundation for building a complete SAF ecosystem in India from feedstock to production to end-use UNITED

TruAlt Bioenergy Managing Director Vijay Nirani said, "At first glance, the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2026 may appear to be a technical update, but it marks a very important shift in India's energy direction."

By formally allowing ATF to be blended with synthesised hydrocarbons, he added that the policy has created a "clear pathway for SAF to be-

come part of the mainstream aviation ecosystem."

For the industry, this amendment provides much-needed regulatory clarity and confidence for long-term investments. It lays the foundation for building a complete SAF ecosystem in India from feedstock to production to end-use, he added.

OIL MINISTRY UPDATE
The Oil Ministry has also up-

dated the legal procedures for enforcement and compliance.

"The provisions of section 103 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this order," the notification said.

This is expected to push the usage of SAF and will help in reducing crude oil imports, which account for more than 85 per cent of the requirement.

The government has already set a target of achieving 1 per cent SAF blending with jet fuel by 2027, 2 per cent by 2028 and 5 per cent by 2030.

E20 BLENDING

According to All India Distillers Association (AIDA), India's achievement of E20 blending has created a strong foundation for SAF development through the Ethanol-to-Jet (ETJ) pathway, lever-

aging the country's extensive ethanol capacity, existing distillery infrastructure and farmer-linked supply chains.

Deloitte India in its October 2024 report on SAF said that India's estimated surplus of 230 million tonnes (mt) of agricultural residue will be a crucial resource for producing SAF.

This surplus will serve as a vital feedstock for ethanol (2G) production, a key component in the Alcohol-to-Jet (ATJ) technology pathway for SAF manufacturing.

At the same time, ATJ route with ethanol (1G) produced from sugar and grain can provide an initial boost until the technology fully matures.

Municipal solid waste and used cooking oil will contribute to the overall potential.

Alternate feedstock such as sweet sorghum, seaweed and industrial waste can give further impetus to SAF potential with technological maturity, it added.



Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD

DELHI

23 APRIL 2026

Govt allows ethanol blending in aviation fuel

SHUBHANGI MATHUR
New Delhi, 22 April

The government has allowed blending of synthetic or man-made hydrocarbons such as ethanol in aviation turbine fuel (ATF), or jet fuel, amid a push for the use of alternate fuels in the wake of the energy crisis triggered by the West Asia conflict.

It has amended the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, under the Essential Commodities Act, 1955, to broaden the definition of ATF to include blends with synthetic hydrocarbons.

According to the government notification, ATF is now defined as



a complex mixture of hydrocarbons conforming to IS 1571 specification or its blend with synthesised hydrocarbons as specified in IS 17081. The revised definition allows blending of alternate fuels such as ethanol with jet fuel.

In India, jet fuel is typically pro-

INDIA AIMS TO BLEND 1% SUSTAINABLE AVIATION FUEL WITH ATF FOR INTERNATIONAL FLIGHTS BY 2027, RAISING IT TO 2% BY 2028 AND 5% BY 2030. HOWEVER, THERE ARE NO BLENDING TARGETS FOR DOMESTIC FLIGHTS AS OF NOW

duced from crude oil. As India faces an energy supply crisis due to the West Asia conflict, the government has introduced measures to boost the use of alternate fuels with the aim of reducing reliance on energy imports.

India aims to blend 1 per cent sustainable aviation fuel (SAF) with jet

fuel for international flights by 2027, raising it to 2 per cent by 2028 and 5 per cent by 2030 in line with the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) mandate. However, there are no blending targets for domestic flights as of now.

SAF is a fuel made from non-petroleum products, including ethanol, which has similar properties to jet fuel but with a much lower carbon footprint.

The latest government notification also updates enforcement provisions to apply search and seizure rules under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.



Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN

DELHI

23 APRIL 2026

रिश्वत केस में डीजीसीए अधिकारी की सीबीआई हिरासत दो दिन बढ़ाई

नई दिल्ली: राज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के उप निदेशक जनरल मुदाबय देवुला और निजी कंपनी के प्रतिनिधि भारत माथुर की भ्रष्टाचार के मामले में दी गई सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी। यह आदेश बुधवार को विशेष न्यायाधीश छवि कपूर ने दिया। सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिन की हिरासत मांगी थी, ताकि आरोपितों से पृष्ठछात्र की जा सके और जांच को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो दिन की ही अतिरिक्त हिरासत मंजूर की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपितों को शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाए और परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए।

सीबीआई के मुताबिक, यह मामला ड्रोन आयात आवेदनों को मंजूरी देने के बदले अवैध लाभ लेने से जुड़ा है। एजेंसी का आरोप है कि हर आवेदन के लिए करीब पांच लाख रुपये की मांग की जा रही थी। सीबीआई ने दोनों आरोपितों को हीज खास के पास से दबेचा था, जहां से उनके पास से 2.5 लाख रुपये बरामद हुए थे। मुदाबय देवुला को ओर से पेश अधिवक्ता तरुण राणा ने दलील दी कि सीबीआई का मौजूदा अर्जी में कोई नए तथ्य नहीं हैं और यह फिजली अर्जी की तरह ही है। भारत माथुर के अधिवक्ता आशीष बत्रा ने कहा कि बरामदगी केवल देवुला से जुड़ी है, ऐसे में माथुर की हिरासत की जरूरत नहीं है।

Govt allows biofuel blending in jet fuel

SAURAV ANAND
New Delhi, April 22

IN A POLICY shift with implications for aviation fuel and energy transition, the Centre has allowed blending of synthetic and alternative hydrocarbons in aviation turbine fuel (ATF), without setting any immediate mandatory blending targets, according to a notification issued by the ministry of petroleum and natural gas.

The amendment to the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, notified on April 17, broadens the definition of jet fuel, enabling the use of sustainable aviation fuel (SAF) and other synthetic blends within the existing regulatory framework.

According to the notification, ATF is now defined as "a complex mixture of hydrocarbons conforming to IS 1571 specification or its blend with synthesised hydrocarbons as specified in IS 17081," effectively opening the sector to newer fuel variants.

The move comes at a time when India is seeking to diversify fuel sources and cut emissions in the aviation sector, even as it continues to depend

LOWERING EMISSIONS



heavily on imported crude oil for its energy needs.

Globally, several countries have moved towards mandatory blending of sustainable aviation fuel to decarbonise air travel. SAF, produced from renewable feedstocks such as waste oils, agricultural residues and municipal waste, can significantly lower emissions compared to conventional jet fuel.

India has outlined indicative targets for SAF blending in international aviation — 1% by 2027, 2% by 2028 and 5% by 2030 — in line with the Carbon Offsetting and Reduction

Scheme for International Aviation. However, no targets have been specified for domestic flights so far.

The notification also revises enforcement provisions by aligning them with the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, replacing earlier legal references related to search and seizure.

"The amendment marks an enabling step for cleaner aviation fuels, but the absence of a mandate indicates that large-scale adoption will depend on future policy direction and market readiness," an industry executive said.



Corporate Communications Directorate

FREE PRESS JOURNAL

MUMBAI

22 APRIL 2026

Bird scare for Air Arabia

HD Bureau
KOCHI

An Air Arabia flight from Abu Dhabi to Thiruvananthapuram came under scrutiny on Tuesday after a suspected bird strike during take-off, but the aircraft continued its journey under standard operating procedures and landed safely in Kerala without incident. Early reports indicated that the suspected impact was detected after departure from Abu Dhabi, with the crew choosing to proceed and complete the service rather than divert. The safe arrival offered immediate reassurance to passengers on a route that is heavily used by Gulf-based workers, families and holiday travellers. The episode did not develop into an emergency on arrival, and there was no indication of injury to



Airlines operating Gulf-Kerala sectors are especially sensitive to operational disruption

passengers or crew. What remained unclear on Tuesday was whether post-flight inspection would confirm an actual strike or classify the event as a precautionary suspicion, a distinction that matters in aviation reporting because crews often rely first on cockpit indications, sounds or external observations before maintenance teams complete checks on the ground.



Corporate Communications Directorate

HARI BHUMI

DELHI

23 APRIL 2026

अकासा एयर के बेड़े में शामिल हुआ नया विमान



नई दिल्ली। अकासा एयर ने एक बोइंग 737 मैक्स 8-200 विमान की आपूर्ति प्राप्त की है। इसके साथ उसके बेड़े में विमानों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। चार महीनों में सात विमान शामिल किए जा चुके हैं। अगस्त 2022 में उड़ान शुरू करने वाली इस एयरलाइन कंपनी ने कहा कि लगातार बेड़े में हो रही बढ़ोतरी से उसका नेटवर्क और मजबूत होगा।



Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN TIMES

DELHI

23 APRIL 2026

दिल्ली और बीजिंग के बीच नॉन स्टॉप उड़ान फिर शुरू

बीजिंग, एजेंसी। चीनी एयरलाइंस एयर चाइना ने अपनी नॉन-स्टॉप दिल्ली-बीजिंग उड़ान फिर से शुरू कर दी है, जिससे दोनों राजधानियों के बीच उड़ान सेवाएं फिर से जुड़ गई हैं।

ये सेवा फिर से शुरू होने के बाद 2020 में कोरोना और लक्ष्मण गतिरोध के बाद बाधित हुई हवाई सेवाएं फिर से बहाल हो गईं। एयरलाइन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बताया, एयर चाइना ने मंगलवार को बीजिंग-दिल्ली को जोड़ने वाली नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर

■ एयर चाइना के विमान
दोनों देशों की राजधानी
को एक-दूसरे से जोड़ेंगे

शुरू की हैं। बीजिंग-दिल्ली उड़ानें मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी। 18 अप्रैल को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत के कुनमिंग व कोलकाता के बीच सीधी उड़ान फिर से शुरू की हैं। भारत की एयरलाइंस भी चीनी शहरों के लिए उड़ानें संचालित कर रही हैं।



Corporate Communications Directorate

MINT

DELHI

23 APRIL 2026

Akasa taps Hajj travel to offset flight cuts

Dipal Banka

dipal.banka@livemint.com

MUMBAI

Akasa Air, India's third-largest airline, is tapping into the month-long demand for Hajj travel to deploy its aircraft capacity left underutilized after services to parts of West Asia were scaled back due to the US-Iran war, according to a person aware of the development.

"About five to six aeroplanes were used on the West Asia route, which are now being used majorly for Hajj travel," the person said, on the condition of anonymity as this plan is part of the business strategy.

Flights to and from Doha, Riyadh, and Kuwait have been suspended until 30 April, according to the airline's 21 April post on X. While it continues to operate flights to Jeddah in Saudi Arabia—the main gateway for pilgrims going to Mecca—from Ahmedabad, Bengaluru, Mumbai, Kochi and Kozhikode, Akasa is evaluating resumption of flights to Abu Dhabi, the post said.

Akasa Air did not respond to *Mint's* queries on aircraft utilization, Hajj travel and the impact of the West Asia war.



About six flights on West Asia routes are being used for Hajj.

The airline has inducted seven new aircraft in 2026, taking the fleet size to 38. However, one of them is undergoing maintenance after a collision at Delhi's Indira Gandhi International Airport with a SpiceJet plane on 16 April.

Experts believe this diversion of idle aircraft can be a temporary fix in the situation, but is not a sustainable option.

Airlines deploying their underutilized aircraft for Hajj travel is a "practical and sensible move" amid the West Asia

disruption, but it is only a short-term fix, said Ashish Chhawchharia, partner and aviation industry leader at Grant Thornton Bharat.

Experts believe diversion of idle aircraft can be a temporary fix in the situation, but not a sustainable option

"While Hajj traffic is huge and provides a strong, concentrated burst of demand, it is limited to a short window of around four to six weeks. That makes it a useful but temporary

cushion. Such deployments help mitigate immediate losses, but they are unlikely to fully offset the sustained impact of reduced West Asia

operations," he said.

Hajj 2026 travel to Mecca in Saudi Arabia begins in April, with the first flights carrying pilgrims having landed in Jeddah on 18 April. This marks the start of the arrival window, which will continue until 21 May, ahead of the main rituals set for 25-29 May.

A more viable fix for airlines would be to explore short-term "wet lease" arrangements for 6-12 months, deploying surplus aircraft to markets that are not affected by the disruption to maintain utilization and generate some revenue, he said. A wet lease agreement is one in which an airline leases its aircraft with crew, maintenance and insurance to another carrier.

On the management side, India's youngest airline is set to induct two new directors to its board, representing key investors Premji Invest and listed asset manager 360 ONE Asset.

Premji Invest and 360 ONE Asset have nominated Manoj Jaiswal and Umesh Devendrakumar Agrawal, respectively, to the board of Akasa Air, said the person quoted above.

For an extended version of this story, go to [livemint.com](https://www.livemint.com).

Air China restores ops, resumes direct flight between Delhi & Beijing

S LALITHA @ New Delhi

AIR China has announced that it has restored operations between Beijing and Delhi since April 21.

In a Facebook post, Air China said it has resumed nonstop flights between Beijing and Delhi. The Beijing-Delhi flights will operate on Tuesdays, Fridays, and Sundays, using Airbus A330-200/300 aircraft.

The post said, "2026 marks the 20th year that Air China has operated in India. Air China's Delhi-Beijing route officially resumed on April 21, with three flights per week operated by Airbus A330-200/300."

It also specified the flight schedule. The plane departs from Beijing at 3:15 pm (local time) and arrives in Delhi at 8:20 pm. The return flight departs Delhi at 10:50 pm and arrives in Beijing the next morning at 7:40 am (local time). "Limited discounts are coming soon," it added. Since April 18, China Eastern Airlines has resumed direct flights between Kunming and Kolkata, operating six days a week. It also plans to launch services between Mumbai and Shanghai, the airline said in an official release.

"The Kunming-Kolkata route holds strategic significance for China Eastern Airlines, facilitating increased trade, tourism,



and cultural exchange between the two countries. Passengers flying via Kunming benefit from seamless connections within China to major hubs such as Shanghai, Beijing Daxing, Guangzhou, Hangzhou, Yiwu, Xiamen, Shenzhen, and Xi'an," the release said.

Airlines from India have already resumed operations to China. IndiGo launched daily direct flights between Kolkata and Shanghai on March 29 this year. Air India resumed nonstop flights between Delhi and Shanghai (PVG) on February 1, 2026, marking a return to mainland China after a nearly six-year suspension. The service operates four times weekly using a Boeing 787 Dreamliner and aims to strengthen trade and tourism ties.

Notably, IndiGo also resumed its operations between Delhi and Guangzhou from November 10 last year.

अब हवाई जहाज़ के ईंधन में भी मिलाया जा सकेगा इथेनॉल केंद्र सरकार ने दी नियमों में ढील, समय-सीमा तय नहीं

■ पीटीआई, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अब विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल - ATF) में इथेनॉल और अन्य सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि, सरकार ने अभी इसके लिए कोई अनिवार्य समय-सीमा या तुरंत लागू होने वाला टारगेट तय नहीं किया है। इस कदम का मकसद प्रदूषण को कम करना और तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को घटाना है।

सरकार ने इसके लिए साल 2001 के 'एविएशन टर्बाइन फ्यूल (मार्केटिंग रेगुलेशन) ऑर्डर' में बदलाव किया है। यह बदलाव आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत किया गया है, जिससे अब ATF की परिभाषा में सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण भी शामिल हो गया है।

फिलहाल, इस मिलावट को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। नए नियमों के



AI Image

मुताबिक, ATF को अब ऐसे मिश्रण के तौर पर परिभाषित किया गया है जो IS 1571 या IS 17081 मानकों पर खरा उतरता हो। इससे अब ईंधन के नए और आधुनिक विकल्पों को विमानों में इस्तेमाल करना मुमकिन हो पाएगा।

आमतौर पर हवाई जहाज का ईंधन कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में, खासकर ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) मिलाने पर जोर

दिया जा रहा है। यह SAF बेकार तेल, चर्बी, चीनी, अनाज, नगर निगम के कचरे, लकड़ी या खेती के अवशेषों से बनाया जाता है। इसे ही सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं।

भारत ने लक्ष्य रखा है कि साल 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन में 1% SAF मिलाया जाएगा। इसे 2028 तक बढ़ाकर 2% और 2030 तक 5% करने का टारगेट है। यह अंतरराष्ट्रीय संस्था CORSIA के नियमों के मुताबिक है। हालांकि, देश के अंदर उड़ने वाली घरेलू फ्लाइट्स के लिए अभी ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा गया है।

CORSIA एक ग्लोबल स्कीम है जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह 2021 से 2026 तक स्वीच्छक है। लेकिन 2027 से 2035 तक ज्यादातर देशों के लिए इसे मानना अनिवार्य हो जाएगा।



Corporate Communications Directorate

NAVBHARAT TIMES

DELHI

23 APRIL 2026

लुफ्थांसा की 20 हजार उड़ानें कम

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ग्रुप ने अपने समर शेड्यूल में दुनिया भर में जाने वाली फ्लाइटों में 20 हजार की कटौती करने का फैसला किया है। इसके पीछे की

भारत में भी
ऐसी कटौती
जल्द देखने
को मिल
सकती है

वजह अमेरिका-
इजराइल और ईरान
युद्ध को बताया जा
रहा है। इसकी वजह
से एविएशन फ्यूल
भी बहुत महंगा हो

गया है। इससे लुफ्थांसा को 40 हजार मीट्रिक टन से अधिक ATF की बचत होने की उम्मीद है। इसी तरह से भारतीय एयरलाइंस भी अपने कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूटों में जल्द ही कटौती कर सकती हैं।

'विमानों में यात्रियों द्वारा' छेड़छाड़, असभ्य व्यवहार और गुंडागर्दी!

किसी समय हवाई यात्रा पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती थी, परंतु कुछ समय से उड़ानों के दौरान नशे में धुत चंद यात्रियों द्वारा हंगामा, धूम्रपान, महिलाओं तथा क्रू मੈम्बर्स से छेड़छाड़, असभ्य व्यवहार और मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जिनके चंद उदाहरण निम्न में दर्ज हैं :

* 9 अप्रैल, 2025 को 'एयर इंडिया' की दिल्ली-बैकाक फ्लाइट में एक यात्री ने महिला यात्री के साथ बदसलूकी की। एयरलाइन ने इसे 'अनरुली बिहेवियर' के रूप में दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी।

* 14 मई, 2025 को 'पर्थ' से 'सिंगापुर' जा रहे 'सिंगापुर एयरलाइंस' के विमान में एक एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने के आरोप में 'रजत' नामक एक भारतीय यात्री को 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

* 28 जून, 2025 को 'एयर इंडिया' की अमृतसर-दिल्ली उड़ान में नशे में धुत एक यात्री ने कैबिन क्रू और सह-यात्रियों के साथ गाली-गलौच तथा हाथापाई की। विमान के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

* 29 जुलाई, 2025 को दुबई से मुंबई आ रहे 'स्पाइस जैट' के विमान में 'मूर्तजा रजाली खान' नामक एक यात्री को विमान के शौचालय में ई-सिगरेट पीते पकड़ा गया।

* 1 अगस्त, 2025 को 'इंडिगो' की मुंबई से कोलकाता जा रही फ्लाइट में एक यात्री ने अपने सह-यात्री को थप्पड़ मार दिया। यात्री को कोलकाता पहुंचने पर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया और 'इंडिगो' ने उस पर कुछ समय तक अपने विमानों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

* 1 अगस्त, 2025 को ही 'इंडिगो' की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में 'मोहम्मद अदनान' नामक यात्री ने 'वाराणसी' में विमान की लैंडिंग से ठीक पहले आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश की। पकड़े जाने पर उसने दावा किया कि उस पर 'भूत' का साया है।

* 1 सितम्बर, 2025 को 'इंडिगो' की दिल्ली-कोलकाता फ्लाइट में एक यात्री ने शराब के नशे में कैबिन क्रू के साथ बदसलूकी की और अन्य यात्रियों को परेशान किया। वह सिगरेट पीने के लिए 'विमान से बाहर' जाने की जिद कर रहा था और बाद में धार्मिक नारे लगाने लगा।

* 16 दिसम्बर, 2025 को हैदराबाद के 'राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे' पर 2 अलग-अलग घटनाओं में यात्रियों को विमान में महिला सह-यात्रियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

* 14 फरवरी, 2026 को 'इंडिगो' की हनोई-कोलकाता फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री से छेड़छाड़ के आरोप में 'मोहम्मद अब्दुर रहमान' नामक व्यक्ति को कोलकाता हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया।

* 7 मार्च, 2026 को दिल्ली से गोवा जा रहे 'अकासा एयर' के एक विमान के शौचालय में एक यात्री को बीड़ी पीने के आरोप में पकड़ा गया। अधिकारियों ने उसके पास से एक लाइटर भी बरामद किया।

* 17 मार्च, 2026 को 'सिंगापुर एयरलाइंस' की 'बैकाक' से 'सिंगापुर' जा रही फ्लाइट के दौरान 'आकाश तिवारी' नामक यात्री को एक एयर होस्टेस से छेड़छाड़ और बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

* 17 अप्रैल, 2026 को सिंगापुर से पर्थ जा रही 'स्कूट एयरलाइंस' की फ्लाइट में 'सुधीर कुमार' नामक एक यात्री को महिला सह-यात्री के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 'सुधीर कुमार' ने महिला सहयात्री से गैर सहमति वाली हरकतें कीं तथा पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर उसे दूसरी सीट पर शिफ्ट किया गया।

उक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि आजकल विमान यात्राएं भी उत्पाती लोगों को शरारतों का शिकार होती जा रही हैं जिससे यात्रियों ही नहीं, बल्कि चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी है। विमानन कंपनियों तथा उनके प्रबंधकों को ऐसे उत्पाती यात्रियों को यात्रा के लिए प्रतिबंधित करने के साथ-साथ इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। —विजय कुमार



Corporate Communications Directorate

THE PIONEER

DELHI

23 APRIL 2026

Lufthansa cuts 20,000 short-haul flights

PIONEER NEWS SERVICE

■ New Delhi

Rising fuel prices are forcing airlines worldwide to recalibrate operations, and Lufthansa Group has emerged as the latest major carrier to respond. The aviation giant has announced plans to cut around 20,000 short-haul flights this summer in a bid to contain costs and improve operational efficiency.

Despite the scale of the reduction, the overall impact on capacity will be minimal. The Group said the cuts will lead to a marginal decline of less than 1 per cent in total capacity, measured in available seat kilometers (ASK).



However, the cost savings are expected to be substantial, with the airline estimating a reduction of more than 40,000 metric tonnes of jet fuel consumption by October.

The decision comes against the backdrop of a sharp spike in global fuel prices, which have reportedly doubled following the escalation of tensions linked

to the Iran conflict escalation. Jet fuel remains one of the largest operating expenses for airlines, and the surge has rendered several short-haul routes economically unviable. In response, Lufthansa is scaling back loss-making routes, particularly from its primary hubs in Frankfurt and Munich, while maintaining broader network connectivity. The airline has emphasised that the move is focused on efficiency rather than a contraction of its global footprint.

While certain routes are being suspended, Lufthansa is simultaneously strengthening operations through alternative hubs such as Zurich, Vienna and Brussels. This

strategy allows the Group to preserve access to long-haul destinations while optimising short-haul connectivity. The restructuring spans all six of Lufthansa's major hubs — Frankfurt, Munich, Zurich, Vienna, Brussels and Rome — and includes operations of its key airlines such as Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines and ITA Airways.

The initial phase of adjustments is already in effect, with approximately 120 daily flights cancelled through May 31. Affected passengers have been informed, and several routes have been temporarily suspended, including services from Frankfurt to cities in Poland and Norway.



Corporate Communications Directorate

THE PIONEER

DELHI

23 APRIL 2026

Air China resumes Delhi-Beijing non-stop flight

KJM VARMA ■ Beijing

Air China has resumed its non-stop Delhi-Beijing flight, reconnecting the flight services between the two capitals. With the resumption of the Delhi-Beijing flight, air connectivity between several cities of the two countries, disrupted since 2020 due to COVID-19 and then the military standoff in Eastern Ladakh, has been restored.

Air China has resumed non-stop flights connecting Beijing and Delhi on Tuesday, the airline said on its Facebook account.

The Beijing-Delhi flights will operate on Tuesdays, Fridays and Sundays, using Airbus A330-200/300 aircraft, the announcement said. On April 18, China Eastern Airlines resumed its direct flight between Kunming, China's southwestern Yunnan Province,



and Kolkata, India.

It was the carrier's latest expansion of its China-India route network following the resumption of the Shanghai-Delhi route in November 2025. China Eastern Airlines said that the route, with six weekly round-trip flights using Boeing 737 aircraft, will add more convenience to travellers between the two countries. India's airlines too are now operating flights to Chinese cities.

IndiGo launched daily

direct flights between Kolkata and Shanghai on March 29. Earlier, IndiGo resumed the Kolkata-Guangzhou route and launched the Delhi-Guangzhou route.

With the introduction of the Kolkata-Shanghai route, IndiGo said it will continue to enrich travel options between China and India, effectively meeting the growing demand for economic, trade, and tourism exchanges between the world's two most populous

nations, China's state-run Global Times reported.

According to the latest operational data for April, IndiGo has maintained an overall passenger load factor between 68 per cent and 85 per cent on multiple China-India routes. Popular routes such as Delhi-Guangzhou and Kolkata-Guangzhou have shown particularly outstanding performances, reflecting a stable and positive operational trend, the report said.

More airlines from both sides are increasing their services, which have positive significance for further consolidating the momentum of bilateral ties.

It also reflects India's further pragmatic adjustments, including in its China policy, Qian Feng, director of the Research Department at Tsinghua University's National Strategy Institute, told the Global Times. (PTI)

Govt gives nod to sustainable aviation fuel, allows blending

ADITI TANDON
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, APRIL 22

In a major shift towards cleaner fuel options for the aviation sector, India on Wednesday granted legal recognition to synthetic and sustainable aviation fuel, allowing blending of alternative components into the fuel basket.

The Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2026, of the Ministry of Petroleum and Natural Gas comes into force immediately.

The amendment, issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, and recently invoked amid the West Asia war, modifies the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001, which has governed the marketing, distribution and supply of jet fuel across India for 25 years.

The changes have implications for India's aviation sector amid national commitments to cleaner aviation fuels and focus on self-reliance to beat supply uncertainties. The most consequential amendment relates to the ATF definition.

The existing definition stands replaced with an



The Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Amendment Order, 2026, comes into force immediately. PHOTO: ISTOCK

expanded one which now reads — "aviation turbine fuel is a complex mixture of hydrocarbons conforming to IS 1571 specification or its blend with synthesised hydrocarbons as specified in IS 17081. The main addition is the explicit recognition of synthesised hydrocarbons — commonly referred to as Sustainable Aviation Fuel or SAF — as a legitimate and legally defined component of aviation turbine fuel in India.

By incorporating a reference to IS 17081 — the Bureau of Indian Standards specification for synthetic aviation fuels — the government has formally brought blended and syn-

thetic jet fuels within the regulatory ambit of the 2001 marketing order.

The notification makes no mention of ethanol but the shift could support biofuel options, including those linked to ethanol.

India has already mandated E20 fuel rollout despite resistance of consumers who have flagged harm to internal combustion engines due to blended options, a fear the government has dismissed. ATF amendments, however, don't set blending targets for the aviation sector.

Officials explain that SAF produced from non-petroleum sources such as agricultural waste like stubble,

municipal solid waste, algae and other biomass, has been identified globally as the single most important tool for reducing carbon emissions from commercial aviation.

"By recognising SAF blends within the legal definition of ATF the government has removed a significant regulatory ambiguity that could have otherwise complicated the procurement, marketing and supply chain management of SAF blends at Indian airports," sources said.

The changed definition provides a legal foundation for airlines and fuel marketing companies to blend, market and supply SAF-mixed jet fuel under the established regulatory framework without requiring fresh legislative action.

This means fuel marketing companies Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum and Bharat Petroleum, primary suppliers of ATF at Indian airports, can now develop commercial frameworks for SAF blending and supply under the established legal structure.

Also, the move will reduce fossil fuel dependence. India imports 87 per cent of this requirement.